COMMERCIAL UNIT



U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. 14th floor, Shakti Bhawan Extn. Lucknow-226001 Tel/Fax- 0522-2287030

CIN:U40101UP1980SGC005065 E-mail: gm.commercial@uprvunl.org

पत्रांक

/ उनिलि / मु०अभि० (वा०) / एल०एम०वी०-10

दिनांक 10,अगस्त, 2016

मुख्य अभियंता (स्तर-।/।) अनपरा/ओबरा/पनकी/पारीछा/हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, सोनभद्र/कानपुर/झॉसी/अलीगढ ।

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० ८वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।

विषय : मा० विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 01.08.2016 के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिये घोषित रेट शिड्यूल/LMV-10 की अधिसूचना दिनांक 06.08.2016 को लागू करने के सम्बन्ध में ।

अवगत कराना है कि मा0 विद्युत नियामक आयोंग के आदेश दिनांक 01.08.2016 के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2016—17 के लिये रिटेल टैरिफ रेट शिड्यूल, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि0 की अधिसूचना सं0 200/एच०सी०/यू०पी०पी०सी०एल०/पाँच—1974—1204—सी/2016 दिनांक 06.08.2016 द्वारा निर्गत कर दिया गया है। इस टैरिफ आदेश के अर्न्तगत निर्गत रेट शिडयूल/LMV-10 की पुनरीक्षित दरें दिनांक 10.08.2016 से निगम के समस्त कार्मिकों पर लागू होंगी।

उक्त के तारतम्य में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत उपरोक्त अधिसूचना की प्रति संलग्नाकों सहित आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों को इसे अवगत कराते हुये पुनरीक्षित दरों को लागू किया जाना सूनिश्चित करने का कष्ट करें ।

अधिसूचना एवं सम्बन्धित रेट शिड्यूल की प्रति उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की वेब साइट <u>www.uprvunl.org</u> पर उपलब्ध है । इसकी प्रतिलिपि ई—मेल द्वारा भी आपको प्रेषित की जा रही है । संलग्नक:— <mark>यथोपरि</mark>

(श्यामं नारायण) मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक)

पत्रांक ५५१ / उनिलि / मु०अभि० (वा०) / एल०एम०वी०-10

दिनांक 10, अगस्त, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1 प्रबन्ध निदेशक महोदय के निजी सहायक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिं०, 7वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2 निदेशक (परि० एवं वाणिज्य / वित्त / कार्मिक / तकनीकी) उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, ८वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

COMMERCIAL UNIT



U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. 14th floor, Shakti Bhawan Extn. Lucknow-226001 Tel/Fax- 0522-2287030 CIN: U40101UP1980SGC005065

E-mail: gm.commercial@uprvunl.org

3. मुख्य अभियंता (स्तर–।/।।), पी०पी०एम०एम०/तापीय परिचालन/मा०सं०/आर०एण्ड एम०/ईंधन/जानपद (नव परि०)/ पर्यावरण व सुरक्षा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ७वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

्र प्रोजेक्ट मैनेजर (प्रगति) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु ।

6. मुख्य प्रबन्धक, कैश मैनेजमेन्ट यूनिट, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 7वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार्ट्र लखनऊ।

7. LMV-10 फाइल ।

(श्याम नीरायन

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ''वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा'' चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522-2287842, फैक्स : 0522-2287834 ई--गेल : cecomuppcl@gmail.com CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक:-

/एच0सी०/टैरिफ/2016-17

दिनांक/अगस्त,

2016

विषय :- मा० विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 01.08.2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए घोषित रेट् शिड्यूल लागू करने के सम्बन्ध में।

ई-मेल/

प्रबन्ध निदेशक स्पीड पोस्ट पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 मेरठ / लखनऊ / आगरा / वाराणसी ।

प्रबन्ध निदेशक केस्को कानपुर।

महोदय.

कृपया अवगत कराना है कि मा० विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 01.08.2016 को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए टैरिफ आदेश निर्गत कर दिया गया है। टैरिफ आदेश के अन्तर्गत निर्गत रेट् शिड्यूल को लागू करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना दिनांक 03.08.2016 को प्रकाशित हो चुकी है। पुनरीक्षित दरें दिनांक 10.08.2016 से प्रभावी होंगी।

तारंतम्य में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत अधिसूचना उक्त के 200 / एच०सी० / यूपीपीसीएल / पांच-1974-1204-सी / 2016 दिनांक 06.08.2016 की प्रति संलग्नकों सहित आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया अपने स्तर से अपने डिस्काम के अधीन समस्त अधिकारियों को इसे उपलब्ध कराते हुए पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त नये रेट् शिड्यूल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बिलिंग साफ्टवेयर में ससमय आवश्यक परिवर्तन करवाना भी अपने स्तर से सुनिश्चित करने की कृपा करें। अधिसूचना की प्रतिलिपि ई-मेल द्वारा भी आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- यथोपरि।

No. 1692 Dir. (Proj. & Com.)/UNL

भवदीय,

(एं०के० पाठक) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा

संख्या : 🔎 / एच0सी0 / टैरिफ / 2016—17 / तद्दिनांक : 🔞 - 🞖 - 💐 । 6

प्रतिलिपि संलग्ज्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

सद्भितः अर्था विद्युत नियामक आयोग, किसान मण्डी भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।

प्रबन्ध्र निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्सिमशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

र्म्स्यत निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

्रिनेजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्रo पावर कारपोरेशन लिo, लखनऊ।

स्रील⁹नक : यथोपरि।

(ए०के० पाठक) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा



उ०प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम) शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या : २०० / एच०सी० / यूपीपीसीएल / पांच-1974-1204-सी / 2016 दिनांक : अगस्त 💪 , 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम—1999 की धारा—24 एवं विद्युत अधिनियम—2003 की धारा 61 एवं 62 के अधीन शक्तियों एवं इस सम्बन्ध में अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके इस विषय पर पूर्व पारित समस्त आदेशों / अधिसूचनाओं द्वारा अनुदेशों का अतिक्रमण करके उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेश दिनांक 01.08.2016 के अनुरूप उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 यह अधिसूचित करता

एतद्द्वारा संलग्न दर अनुसूचियाँ एवं विविध प्रभारों की अनुसूची उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत (क)^{*} समस्त सरकारी वितरण कम्पनियों द्वारा पोषित समस्त उपभोक्ताओं पर प्रभावी होंगी।

रेग्युलेटरी सरचार्ज-1 : माननीय आयोग के आदेश दिनांक 18.04.2016 द्वारा समाप्त।

मा० नियामक आयोग के टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2016-17, दिनांक 01.08.2016 के अनुपालन में 4.28% की दर से दक्षिणांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम क्षेत्र एवं 3.03% की दर से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा रेग्यूलेटरी सरचार्ज-2 देय होगा।

मा० नियामक आयोग के टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2016-17, दिनांक 01.08.2016 के अनुपालन में केस्को, कानपुर के घरेलू बत्ती पंखा एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा 3.91% तथा अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा 4.13% की दर से रेग्यूलेटरी सरचार्ज-2 देय होगा।

(क) और (ख) में उल्लिखित दरें / प्रभार दिनांक 10.08.2016 से प्रभावी होंगी। (ग)

प्रतिबन्ध यह है कि अधिसूचना के लागू होने की तिथि के पश्चात् उपभोक्ताओं द्वारा किया गया विद्युत उपभोग, जो मीटर रीडिंग द्वारा प्रथम बार अंकित किया जाएगा, उपभोग की गयी अवधि के अनुपात में पुराने एवं नये दर के अनुसार बाँट दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर उ०प्र० शासन एवं/अथवा उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा आदेशित ऐसे प्रभार अथवा अधिभार एवं विद्युत शुल्क के लागू किए जाने के प्रतिबन्धाधीन संशोधित

दर सूचियाँ लागू होगी।

पूर्वगत प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अतिरिक्त संलग्न अनुसूचियों में उल्लिखित शुल्क दरें, विद्यत सम्पूर्ति शर्ते एवं अन्य विषय, वर्तमान दर अनुसूचियों द्वारा पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद / उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / समस्त सरकारी वितरण कम्पनियों के साथ हुए वर्तमान अनुबन्धों में यदि कोई हो, विद्यमान दर अनुसूचियों द्वारा तत्कालीन व्यवस्थाओं को दिनांक 10.08.2016 से प्रतिस्थापित करेंगे।

संलग्नक : यथोपरि।

आज्ञा से,

(संजय अग्रवील)

अध्यक्ष

उ०प्र0पा०का०लि०. मध्यांचल,पूर्वांचल,दक्षिणांचल,पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को



U.P. POWER CORPORATION LIMITED (U.P. GOVT. UNDERTAKING) SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG LUCKNOW.

No. 260 /H.C./UPPCL/V-1974-1204-C/2016

Dated: August 6, 2016

NOTIFICATION

In conformity of tariff order dated 01.08.2016 issued by U.P. Electricity Regulatory Commission in exercise of powers under section 24 of the Electricity Reforms Act, 1999 and section 61 and 62 of Electricity Act-2003 and all other power in this behalf and in supersession of all previous notifications, orders and instructions on the subject, U.P. Power Corporation Ltd. hereby notify that:-

- (A) The revised rate schedules and schedule of miscellaneous charges appended hereto, shall apply to all consumers in respect of supply of electricity throughout the area of supply of all Government owned distribution companies in the state of Uttar Pradesh.
- (B) (i) Regulatory Surcharge-1 has been abolished vide UPERC order dated 18.04.2016.
 - (ii) Regulatory Surcharge-2 @ 4.28% shall be levied on the consumers in the supply area of DVVNL, MVVNL, PuVVNL and @ 3.03% in supply area of PVVNL.
 - (iii) For KESCO, Regulatory Surcharge-2@ 4.13% (for all categories except LMV-1 & LMV-5) shall be applicable. Consumer of category LMV-1 & LMV-5 shall be levied Regulatory Surcharge-2@3.91%.
- (C) The rates/charges as specified in (A) and (B) above shall come into force w.e.f. 10.08.2016.

Provided that the consumption of consumers recorded through meter reading taken for the first time, after the effective date of this notification, will be bifurcated on pro-rata basis between old tariff and new tariff.

- 2. The revised rate schedules shall, besides, be subject to levy of such charges or surcharges and electricity duty as may be imposed by the Government and/or UPERC from time to time.
- In addition to condition mentioned in para-2 above, the rates of charge; conditions of supply and other matters specified in the schedules annexed hereto, shall replace the existing rates of charge and corresponding provisions in the existing rate schedules and in the existing agreements, if any, with the erstwhile UPSEB/U.P. Power Corporation Ltd/all Government owned distribution companies, w.e.f. 10.08.2016.

Annexure: As above.

(Saniav Agarwal)

By Order.

Chairman UPPCL,MVVNL,DVVNL, PVVNL,PuVVNL, KESCO

RATE SCHEDULE FOR FY 2016-17

RETAIL TARIFFS FOR FINANCIAL YEAR 2016-17

GENERAL PROVISIONS:

These provisions shall apply to all categories unless specified otherwise and are integral part of the Rate Schedule.

1. NEW CONNECTIONS:

(i) All new connections shall be given as per the applicable provisions of Electricity Supply Code and shall be released in multiples of KW only, excluding consumers under categories LMV-5 & LMV-8 of Rate Schedule. Further, for tariff application purposes, if the contracted load (kW) of already existing consumer is in fractions then the same shall be treated as next higher kW load.

READING OF METERS:

As per applicable provisions of Electricity Supply Code.

3. BILLING WHEN METER IS NOT MADE ACCESSIBLE:

A penalty of Rs. 50 / kW or as decided by the Commission through an Order shall be levied for the purposes of Clause 6.2 (c) of the applicable Electricity Supply Code.

4. BILLING IN CASE OF DEFECTIVE METERS:

As per the applicable provisions of Electricity Supply Code.

5. KVAH TARIFF:

'kVAh based tariffs' shall be applicable on all consumers having contracted load of $10\,$ kW / $13.4\,$ BHP and above, under different categories with TVM / TOD / Demand recording meters (as appropriate).

The rates prescribed in different categories in terms of kW and kWh will be converted into appropriate kVA and kVAh by multiplying Fixed / Demand Charges and Energy Charges by an average power factor of 0.90. Similarly, the Fixed / Demand Charges expressed in BHP can be converted into respective kVA rates in accordance with formula given below:

Demand Charges in kVA = (Demand Charges in BHP / 0.746) * 0.90

Demand Charges in kVA = (Fixed Charges in kW * 0.90)

Energy Charges in kVAh = (Energy Charges in kWh * 0.90)

Note: If the power factor of a consumer is leading and is within the range of 0.95 -1.00, then for tariff application purposes such leading power factor shall be treated as unity. The bills of such consumers shall be prepared accordingly. However, if the leading power factor is below 0.95 (lead) then the consumer shall be billed as per the kVAh reading indicated by the meter. However, the aforesaid provision of treating power factor below 0.95 (lead) as the commensurate lagging power factor for the purposes of billing shall not be applicable on HV-3 category and shall be treated as unity. Hence, for HV-3, lag + lead logic of the meter should not be used and "lag only" logic of the meter should be provided which blocks leading kVARh thereby treating leading power factor as unity and registering instantaneous kWh as instantaneous kVAh in case of leading power factor.

BILLABLE LOAD / DEMAND:

For all consumers having TVM / TOD / Demand recording meters installed, the billable load / demand during a month shall be the actual maximum load / demand as recorded by the meter (can be in parts of kW or kVA) or 75% of the contracted load / demand (kW or kVA), whichever is higher.

Further in case the licensee fails to note the actual maximum load / demand reading or in case of spot-billing, then the consumer may approach the licensee with a photo of the actual maximum load / demand reading displayed on his meter of the previous month. The licensee shall accept the same for the purpose of computation of billable demand, however if the licensee wishes to, it can get the same verified within 10 days.

SURCHARGE / PENALTY:

(i) DELAYED PAYMENT:

If a consumer fails to pay his electricity bill by the due date specified therein, a late payment surcharge shall be levied at 1.25% per month; upto first three months of delay and subsequently @ 2.00% per month of delay. Late payment surcharge shall be calculated proportionately for the number of days for which the payment is delayed beyond the due date specified in the bill and levied on the unpaid amount of the bill excluding surcharge. Imposition of this surcharge is without prejudice to the right of the Licensee to disconnect the supply or take any other measure permissible under the law.

(ii) CHARGES FOR EXCEEDING CONTRACTED DEMAND:

- If the maximum load / demand in any month of a domestic consumer having TVM / TOD / Demand recording meter exceeds the contracted load / demand, then such excess load / demand shall be levied equal to 100% of the normal rate apart from the normal fixed / demand charge as per the maximum load / demand recorded by the meter. Further, if the consumer is found to have exceeded the contracted load / demand for continuous previous three months, the consumer shall be served a notice of one month advising him to get the contracted load enhanced as per the provisions of UPERC Electricity Supply Code, 2005 and amendments thereof. However, the consumer shall be charged for excess load for the period the load is found to exceed the contracted load. The Licensee shall merge the excess load with the previously sanctioned load, and levy additional charges calculated as above, along with additional security. Subsequent action regarding the increase in contracted load, or otherwise shall be taken only after due examination of the consumer's reply to the notice and a written order in this respect by the Licensee.
- b. If the maximum load / demand in any month, for the consumers of other category(except (a) above) having TVM/ TOD /Demand recording meter exceeds the contracted load /demand , then such excess load /demand shall be levied equal to 200% of the normal rate apart from the normal fixed /demand charges as per the maximum load /demand recorded by the meter.
- c. Any surcharge / penalty shall be over and above the minimum charge, if the consumption bill of the consumer is being prepared on the basis of minimum charge.
- d. Provided where no TVM / TOD / Demand recording meter is installed, the excess load / demand penalty shall be billed as per the UPERC Electricity Supply Code, 2005 as amended from time to time.

8. POWER FACTOR SURCHARGE:

- (i) Power factor surcharge shall not be levied where consumer is being billed on kVAh consumption basis.
- (ii) It shall be obligatory for all consumers to maintain an average power factor of 0.85 or more during any billing period. No new connections of motive power loads / inductive loads above 3 kW, other than under

LMV-1 and LMV-2 category, and / or of welding transformers above 1kVA shall be given, unless shunt capacitors having I.S.I specifications of appropriate ratings are installed, as described in ANNEXURE-III.

(iii) In respect of the consumers with or without static TVMs, excluding consumers under LMV-1 category up to contracted load of 10 kW and LMV-2 category up to contracted load of 5 kW, if on inspection it is found that capacitors of appropriate rating are missing or in-operational and Licensee can prove that the absence of capacitor is bringing down the power factor of the consumer below the obligatory norm of 0.85; then a surcharge of 15% of the amount of bill shall be levied on such consumers. Licensee may also initiate action under the relevant provisions of the Electricity Act, 2003, as amended from time to time.

Notwithstanding anything contained above, the Licensee also has a right to disconnect the power supply, if the power factor falls below 0.75.

(iv) Power factor surcharge shall however, not be levied during the period of disconnection on account of any reason whatsoever.

PROTECTIVE LOAD:

Consumers getting supply on independent feeder at 11kV & above voltage, emanating from sub-station, may opt for facility of protective load and avail supply during the period of scheduled rostering imposed by the Licensee, except under emergency rostering. An additional charge @ 100% of base demand charges fixed per month shall be levied on the contracted protective (as per Electricity Supply Code) load each month. However, consumers of LMV-4 (A) - Public Institutions will pay the additional charge @ 25% of base demand charges only. During the period of scheduled rostering, the load shall not exceed the sanctioned protective load. In case the consumer exceeds the sanctioned protective load during scheduled rostering, he shall be liable to pay twice the prescribed charges for such excess load.

10. ROUNDING OFF:

All bills will be rounded off to the nearest rupee i.e. up to 49 paisa shall be rounded down to previous rupee and 50 paisa upwards shall be rounded up to next rupee. The difference due to such rounding shall be adjusted in subsequent bills.

11. OPTION OF MIGRATION TO HV-1 & HV-2 CATEGORY:

The consumer under LMV-2 and LMV-4 with contracted load above 50 kW and getting supply at 11 kV & above voltage shall have an option to migrate to the HV-1 category and LMV-6 consumers with contracted load above 50 kW and getting supply at 11 kV & above voltage shall have an option to migrate to the HV-2

category. Furthermore, the consumers shall have an option of migrating back to the original category on payment of charges prescribed in Cost Data Book for change in voltage level.

12. PRE-PAID METERS / AUTOMATIC METER READING SYSTEM:

- (i) Any consumer having prepaid meters shall also be entitled to a discount of 1.25% on Rate as defined in the Tariff Order.
- (ii) The token charges for code generation for prepaid meters shall be Rs. 10/per token or as decided by the Commission from time to time.

13. CONSUMERS NOT COVERED UNDER ANY RATE SCHEDULE OR EXPRESSLY EXCLUDED FROM ANY CATEGORY:

For consumers of light, fan & power (excluding motive power loads) not covered under any rate schedule or expressly excluded from any LMV rate schedule will be categorized under LMV-2.

14. A consumer under metered category may undertake any extension work, in the same premises, on his existing connection without taking any temporary connection as long as his demand does not exceed his contracted demand and the consumer shall be billed in accordance with the tariff applicable to that category of consumer.

15. SOLAR WATER HEATER REBATE:

If consumer installs and uses solar water heating system of 100 litres or more, a rebate of Rs. 100 /- per month or actual bill for that month whichever is lower shall be given. The same shall be subject to the condition that consumer gives an affidavit to the licensee to the effect that he has installed such system and is in working condition, which the licensee shall be free to verify from time to time. If any such claim is found to be false, in addition to punitive legal action that may be taken against such consumer, the licensee will recover the total rebate allowed to the consumer with 100% penalty and debar him from availing such rebate for the next 12 months.

16. REBATE ON PAYMENT ON OR BEFORE DUE DATE:

A rebate at 0.50% of Rate shall be given in case the payment is made on or before the due date. The consumers having any arrears in the bill shall not be entitled for this rebate. The consumers who have made advance deposit against their future monthly energy bills shall also be eligible for the above rebate applicable on Rate.

17. REBATE TO CONSUMERS WHO SHIFT FROM UNMETERED TO METERED CONNECTION:

In case any rural consumer shifts from unmetered to metered category, he shall be entitled to rebate of 10% on Rate which shall be applicable from date of installation of meter till end of FY 2017-18.

18. SCHEME FOR ADVANCE DEPOSIT FOR FUTURE MONTHLY ENERGY BILLS:

If a consumer intends to make advance deposit against his future monthly energy bills, the Licensee, shall accept such payment and this amount shall be adjusted only towards his future monthly energy bills. On such advance deposit the consumers shall be paid interest, at the interest rate applicable on security deposit, for the period during which advance exists for each month on reducing balance method and amount so accrued shall be adjusted in the electricity bills which shall be shown separately in the bill of each month. Further, quarterly report regarding the same must be submitted to the Commission.

19. FACILITATION CHARGE FOR ONLINE PAYMENT:

- (i) No transaction charge shall be collected from the consumers making their payment through internet banking.
- (ii) The Licensees shall bear the transaction charges for transactions up to Rs. 4,000 for payment of bill through internet using Credit Card / Debit Card.

20. MINIMUM CHARGE:

Minimum charge is the charge in accordance with the tariff in force from time to time and come into effect only when sum of fixed / demand charges and energy charges are less than a certain prescribed amount i.e. Minimum Charges. For each month, consumer will pay an amount that is higher of the following:

- (i) Fixed / Demand charges plus Energy Charge on the basis of actual consumption for the month and additional charges such as Electricity Duty, Regulatory Surcharges, FPPCA Surcharges and any other charges as specified by the Commission from time to time.
- (ii) Monthly minimum charge as specified by the Commission and computed at the contracted load and additional charges such as Electricity Duty, Regulatory Surcharges, FPPCA Surcharges and any other charges as specified by the Commission from time to time.

21. EXEMPTION FROM MINIMUM CHARGE FOR USING SOLAR POWER:

If a consumer under LMV-2 (Non domestic light, fan and power) category installs a rooftop solar plant under the provisions of UPERC (Rooftop Solar PV Grid Interactive Systems Gross / Net Metering) Regulations, 2015 with maximum peak capacity of the grid connected rooftop solar PV system not exceeding 100% of the sanctioned connected load / contract demand of the consumer, then such consumer shall be exempted from payment of monthly minimum charges. Such exemption shall be in force till the time the solar plant remains fully operational.

22. INTEREST ON DUES PAYABLE TO CONSUMER BY THE LICENSEE:

If a consumer becomes eligible for dues from the Licensee which may arise out of rectification / adjustment / settlement of bill(s), then such consumer will also be entitled to get interest at an interest rate applicable for interest on security deposits on all the dues payable by the Licensee to the consumer. The Licensee shall compute the interest amount for the period during which such pending amounts exists and adjust such interest towards the future monthly bills of consumers. After adjustment of the interest amount in a particular month, the balance amount, will be carried forward to next month for adjustment with interest on balance amount. The details of such interest amount and adjustment made during the month shall be shown separately in the bill. Further, separate accounting of interest paid must be maintained by the Licensees.

23. DEFINITION OF RURAL SCHEDULE:

Rural Schedule means supply schedule as defined and notified by State Load Despatch Centre (SLDC), Lucknow from time to time.

RATE SCHEDULE LMV - 1

DOMESTIC LIGHT, FAN & POWER

1. APPLICABILITY:

This schedule shall apply to:

- (a) Premises for residential / domestic purpose, Accommodation for Paying Guests for Domestic purpose (Excluding Guest Houses), Janata Service Connections, Kutir Jyoti Connections, Jhuggi / Hutments, Places of Worship (e.g. Temples, Mosques, Gurudwaras, Churches) and Electric Crematoria.
- (b) Mixed Loads
- i. 50 kW and above
- a. Registered Societies, Residential Colonies / Townships, Residential Multi-Storied Buildings with mixed loads (getting supply at single point) with the condition that at least 70% of the total contracted load shall be exclusively for the purposes of domestic light, fan and power. The above mixed load, within 70%, shall also include the load required for lifts, water pumps and common lighting,
- b. Military Engineer Service (MES) for Defence Establishments (Mixed load without any load restriction).

ii. Less than 50 kW

Except for the case as specified in Regulation 3.3 (e) of Electricity Supply Code, 2005 as amended from time to time, if any portion of the load is utilized for conduct of business for non-domestic purposes then the entire energy consumed shall be charged under the rate schedule of higher charge

2. CHARACTER AND POINT OF SUPPLY:

As per the applicable provisions of Electricity Supply Code.

3. RATE:

Rate, gives the fixed and energy charges at which the consumer shall be billed for his consumption during the billing period applicable to the category:

(a) Consumers getting supply as per 'Rural Schedule':

Description	Description	Fixed charge	Energy charge)
odi in omne Grant stimulai	Load up to 2 kW	Rs. 180 / kW / month	Nil
i) Un-metered	Load above 2 kW	Rs. 200 / kW / month	Police Nil
ii) Metered	All Load	Rs. 50 / kW / month	Rs. 2.20 / kWh

(b) Supply at Single Point for bulk loads (50 kW and above, Supplied at any Voltage):

Description	Fixed Charge	Energy Charge
For Townships, Registered Societies, Residential Colonies, multi-storied residential complexes (including lifts, water pumps and common lighting within the premises) with loads 50 kW and above with the restriction that at least 70% of the total contracted load is meant exclusively for the domestic light, fan and power purposes and for Military Engineer Service (MES) for Defence Establishments (Mixed load without any load restriction).	Rs. 85.00 / kW / Month	Rs. 5.50 / kWh

The body seeking the supply at Single point for bulk loads under this category shall be considered as a deemed franchisee of the Licensee. Such body shall charge not more than 5% additional charge on the above specified 'Rate' from its consumers apart from other applicable charges such as Regulatory Surcharge, Penalty, Rebate and Electricity Duty on actual basis.

The 5% additional charge shall be towards facilitating supply of electricity to the individual members to recover its expenses towards supply of electricity, distribution loss, electrical maintenance in its supply area, billing, accounting and audit etc.

The deemed franchisee is required to provide to all its consumers and the licensee, a copy of the detailed computation of the details of the amounts realized from all the individual consumers and the amount paid to the licensee for every billing cycle on half yearly basis. If he fails to do so, then the consumers may approach

the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) having jurisdiction over their local area for the redressal of their grievances.

The deemed franchisee shall arrange to get its account(s) audited by a Chartered Accountant mandatorily. The audited accounts will be made available to all the consumers of the deemed franchisee within 3 months of the closure of that financial year. If he fails to do so, then the consumers may approach the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) having jurisdiction over their local area for the redressal of their grievances.

The deemed franchisee should separately meter the electricity supplied from back up arrangements like DG sets etc. The bill of its consumers should clearly depict the units and rate of electricity supplied through back up arrangement and electricity supplied through Licensee.

The deemed franchisee shall not disconnect the supply of electricity of its consumers on the pretext of defaults in payments related to other charges except for the electricity dues regarding the electricity consumed by its consumers and electricity charges for lift, water lifting pump, streetlight if any, corridor / campus lighting and other common facilities.

In case the deemed franchisee exceeds the contracted load / demand under the provisions of Clause 7(ii) — 'Charges for Exceeding Contracted demand' of the General Provisions of this Rate Schedule, only in such case the deemed franchisee will recover the same from the individual members who were responsible for it on the basis of their individual excess demands.

(c) OTHER METERED DOMESTIC CONSUMERS:

 Lifeline consumers: Consumers with contracted load of 1 kW, energy consumption up to 150 kWh / month.

Description	Fixed Charge	Energy Charge	
Loads of 1 kW only and for consumption up to 50 kWh / month (0 to 50 kWh / month)	Rs. 50.00 / kW / month	Rs. 2.00 / kWh	
Loads of 1 kW only and for consumption above 50 kWh / month up to 150 kWh / month (51 to 150 kWh / month)		Rs. 3.90 / kWh	

2. Others: Other than life line consumers (i.e. consumers who do not qualify under the criteria laid down for lifeline consumers.)

Description	Consumption Range	Fixed Charge	Energy Charge
	For first 150 kWh / month	*1:20000	Rs. 4.40 / kWh
	For next 151 - 300 kWh / month	Rs. 4.95 / kWh	
All loads	For next 301 – 500 kWh / month	Rs. 90.00 / kW / month	Rs. 5.60 / kWh
	For above 500 kWh / month (Starting from 501 st unit)		Rs. 6.20 / kWh

Note:

1. For all consumers under this category the maximum demand during the month recorded by the meter has to be essentially indicated in their monthly bills. However, this condition would be mandatory only in case meter reading is done by the Licensee. Accordingly, if the bill is being prepared on the basis of reading being submitted by the consumer then the consumer would not be liable to furnish maximum demand during the month and his bill would not be held back for lack of data of maximum demand.

RATE SCHEDULE LMV-10

DEPARTMENTAL EMPLOYEES AND PENSIONERS

1. APPLICABILITY:

This schedule shall apply only to such employees (including the cases of retired / voluntary retired or deemed retired) of Licensees / successor entities of erstwhile Uttar Pradesh State Electricity Board (UPSEB), who own electricity connection in their own name and opt for the same for their own use for light, fan and power for domestic appliances, where the energy is being fed directly from Licensee mains. The Schedule shall also apply to spouse of employees served under Licensees / successor entities of erstwhile UPSEB.

2. RATE:

On all such consumers LMV-1 rate schedule will be applicable. However the Licensees are authorised to provide "rebate" as they deem fit to the consumers eligible to get supply under this category.

3. ELECTRICITY DUTY:

Electricity duty on the above shall be levied in addition at the rates as may be notified by the State Government from time to time.

4. OTHER PROVISIONS:

- i. For serving / retired employees and their spouse, the supply will only be given at one place where Licensee's mains exist. The electric supply under this tariff will be given only at one place, within the area of erstwhile UPSEB / its successor companies.
- ii. Concerned executive engineers will take an affidavit from all employees and pensioners that the electricity supplied to their premises is being used exclusively for the purpose of domestic consumption of themselves and

their dependants. It will have to be certified by the employees/pensioners that such electricity is not being used for any other purpose or to any individual to whom his house has been rented out. Without any prejudice to any legal action as provided in the legal framework, any misuse to above effect shall invalidate him from the facility of LMV-10 on permanent basis.

- iii. In the event of transfer of the employee, this tariff shall be applied at the new place of posting only when a certificate has been obtained from the concerned Executive Engineer of the previous place of posting, that the supply under this tariff has been withdrawn at previous place of posting. Further, the employee shall also be required to submit an affidavit that he is not availing the benefit of LMV-10 connection anywhere else in the state.
- iv. Those who are not availing this tariff shall also give a declaration to this effect. This declaration shall be pasted / kept in his service book / personal file / Pensioners record. If the declaration is found wrong, necessary action against the employee shall be taken as per the provisions of service rules. If declaration has already been given at the present place of posting then further declaration is not necessary due to this revision. Pensioners shall also have to give a similar declaration for availing departmental tariff at only one place. In case this declaration is found wrong, this tariff shall be withdrawn forever.
- v. No other concession shall be admissible on this tariff.
- vi. The schedule of miscellaneous charges as appended with Licensee's General Tariff as amended from time to time and Electricity Supply (Consumers) Regulation, 1984 as enforced from time to time shall also be applicable on the employee / pensioner receiving supply under this schedule.
- vii. Retired employees drawing pension from the Treasury / Bank will have to pay the monthly electricity charges as per the rates given in the rate schedule applicable to their category.